

उत्तर पूर्व औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 पर संक्षिप्त विवरण

अधिसूचना: - एनईआईआईपीपी, 2007 को उत्तर पूर्व औद्योगिकनीति (एनईआईपी), 1997 के संशोधन पर 01.04.2007 को अधिसूचित किया गया था।

कवरेज: - उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के तहत मान्यता प्राप्त आठ पूर्वोत्तर राज्य।

पात्रता और अवधि: - सभी नई इकाइयों के साथ-साथ मौजूदा औद्योगिक इकाइयां जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कहीं भी स्थित हैं और अपना औद्योगिक विस्तार करना चाहती हैं और यदि वे एनईआईआईपीपी, 2007 की अधिसूचना तिथि से 10 वर्षों के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करती हैं तो वे 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।

इस योजना का लाभ सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक माने जाने वाले उद्योग जैसे तम्बाकू और इसके पूरक उत्पाद, पान मसाला, 20 माइक्रोनसे कम के प्लास्टिक बैग, रिफाइनरी उत्पाद आदि को नहीं दिया जाएगा।

विनिर्माण क्षेत्र के अलावा, एनईआईआईपीपी, 2007 के तहत दिए जाने वाले लाभों को पहली बार सेवा क्षेत्र में भी दिया गया है, (यानी दो सितारा श्रेणी से उच्च होटल, साहसिक और लेजर स्पोर्ट्स जिनमें रोपवे भी शामिल हैं, 25 बेड की न्यूनतम क्षमता वाले नर्सिंग होम, वृद्धाश्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान जैसे होटल प्रबंधन, खानपान और खाद्य शिल्प, उद्यमिता विकास, नर्सिंग और पैरा-मेडिकल, नागरिक उड्डयन से संबंधित प्रशिक्षण, फैशन, डिजाइन और औद्योगिक प्रशिक्षण, जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग और 10 मेगावाट तक के विद्युत उत्पादन उद्योग)।

राजसहायता योजना: - एनईआईआईपीपी, 2007 के तहत राजसहायता योजनाएं और उनकी मुख्य विशेषताएं और

अब तक की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं: -

1. केंद्रीय पूंजीगत निवेश राजसहायता योजना: -

यह योजना पूंजीगत निवेश जैसे संयंत्र और मशीनरी के मूल्य का बिना किसी ऊपरी सीमा के 30% राजसहायता प्रदान करती है। राजसहायता के स्वतः अनुमोदन की सीमा रु. 1.50 करोड़ है; रु 1.50 करोड़ से रु.30 करोड़ तक की मंजूरी का अनुमोदन उच्चाधिकार प्राप्त समिति और रु.30 करोड़ से अधिक का अनुमोदन केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन से दिया जाता है।

230735/2020/डीबीए-॥/एनईआर158

2. केंद्रीय ब्याज राजसहायता योजना: -

यह योजना औद्योगिक इकाई द्वारा लिए गए कार्यशील पूंजी ऋण पर 3% की ब्याज राजसहायता प्रदान करती है। यह ऋण व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से अधिकतम 10 (दस) वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

3. केंद्रीय व्यापक बीमा राजसहायता योजना: -

यह योजना औद्योगिक इकाई द्वारा बीमा प्रीमियम के भुगतान का 100% प्रतिपूर्ति करती है।

अन्य प्रोत्साहन / शर्तें: -

- राजस्व विभाग द्वारा निर्दिष्ट "मूल्यवर्धन" मानदंडों के आधार पर उत्पाद शुल्क में छूट।
- 100% आयकर छूट।

समन्वय और निगरानी: - एनईआईआईपीपी, 2007 के उचित समन्वय और निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति, सलाहकार समितिके साथ निरीक्षण समिति जैसी विभिन्न समितियों का गठन किया गया है।

नोडल एजेंसी: - उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) गुवाहाटी एनईआईआईपीपी, 2007 की विभिन्न राजसहायता योजनाओं के तहत राजसहायता देने के लिए नामित एजेंसी है।

एनईआईआईपीपी, 2007 के तहत जारी राशि: - स्थापना के बाद से, उत्तरी पूर्वी राज्यों को 3036.23 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, उपक्षेके राज्यों को रु.583.52 करोड़ की राशि जारी की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में, एनईआईआईपीपी, 2007 के तहत बीईमें 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
